



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940

No. 48]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 25 जनवरी, 2019

सं. टीएएमपी/59/2014-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा प्राधिकरण के 17 अगस्त, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी और टीएएमपी/59/2014-केपीटी दिनांक 07 जनवरी, 2015 के आदेश में संशोधन के बारे में मैसर्स अडानी कांडला बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एकेबीटीपीएल) से प्राप्त संदर्भ का, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/59/2014-केपीटी

मैसर्स अडानी कांडला बल्क टर्मिनल प्राइवेट लि.

आवेदक

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(जनवरी, 2019 के 18वें दिन पारित)

यह मामला प्राधिकरण के 17 अगस्त, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी और 02 जनवरी, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/59/2014-केपीटी में संशोधन के लिए मैसर्स अडानी कांडला बल्क टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (एकेबीटीपीएल) के 18 जनवरी 2018 के पत्र और 18 जनवरी, 2018 के ई-मेल से प्राप्त संदर्भ से संबंधित है।

2.1. प्राधिकरण ने (तत्कालीन) कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) के प्रस्ताव के आधार पर अप्रकट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अनुसरण में तूना के निकट ऑफ टेकरा स्थित शुष्क बल्क टर्मिनल के विकास के लिए 17 अगस्त, 2010 को पारित आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी के द्वारा अप्रकट प्रशुल्क निर्धारित किये थे। यह आदेश भारत के राजपत्र में 02 नवंबर, 2010 को राजपत्र संख्या 285 के रूप में अधिसूचित हुआ था।

2.2. अप्रकट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के खंड 2.8 और 17 अगस्त, 2010 के उक्त अप्रकट प्रशुल्क आदेश के पैरा 11.1 के अनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अप्रकट प्रशुल्क थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के 60% वार्षिक सूचकांकन के अधीन 30 वर्ष के लिए है।

2.3. डीपीटी ने इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अप्रकट प्रशुल्क पर तूना के निकट ऑफ टेकरा पर शुष्क बल्क टर्मिनल के विकास की परियोजना को एकेबीटीपीएल को दिया था। डीपीटी और एकेबीटीपीएल के बीच 27 जून, 2012 को रियायत करार (सीए) हुआ।

2.4. प्रशुल्क से संबंधित सीए के अनुच्छेद 8.1 के अनुसार, लाइसेंसधारक प्रशुल्क अधिसूचना के अनुसार, परियोजना सुविधाओं और सेवाओं के प्रयोक्ताओं से प्रशुल्क एकत्र करने का पात्र है। इस प्राधिकरण द्वारा 17 अगस्त, 2010 के आदेश के द्वारा अनुमोदित दरमान सीए के परिशिष्ट-12 के रूप में संलग्न है।

2.5. तत्पश्चात्, एकेबीटीपीएल ने अप्रकट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के खंड 2.9.1 और 17 अगस्त, 2010 के आदेश के पैरा 11.2 के अनुसार सूचकांकित दरमानों को अपने नाम से अधिसूचित कराने का प्रस्ताव दायर किया था। तदनुसार, उस प्राधिकरण ने 22 अक्टूबर, 2014 के पत्र संख्या टीएएमपी/59/2014-केपीटी के माध्यम से डीपीटी से परामर्श के पश्चात् अपने 02 जनवरी, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/59/2014-केपीटी के द्वारा 17 अगस्त, 2010 को अधिसूचित अप्रकट प्रशुल्क विधिवत् सूचकांकित दरमानों को एकेबीटीपीएल के नाम से अधिसूचित किया।

3. उक्त आदेश के संदर्भ में, एकेबीटीपीएल ने अपने 18 जनवरी 2018 के पत्र और 18 जनवरी, 2018 के ई-मेल के द्वारा निम्नलिखित निवेदन किये:

- (i). 17 अगस्त, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी और 02 जनवरी, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/59/2014-केपीटी और तत्पश्चात् संशोधनों के संदर्भ में निर्माण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) आधार पर डीपीटी में कांडला क्रीक के बाहर तूना के निकट शुष्क बल्क टर्मिनल के लिए इस प्राधिकरण द्वारा जारी उक्त आदेश में अनभिप्रेत स्पष्ट टंकण भूल हुई है।

- (ii). इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरमान के खंड 3 में कार्गो प्रहस्तन प्रभार निर्धारित किये गए जिन्हें संदर्भ के लिए नीचे पुनरुद्धरित किया जा रहा है और पहले दो वाक्य मोटे रूप में हाइलाइट किये गए हैं:

3. नौभार प्रहस्तन प्रभार:

सूचीबद्ध नौभार संबंधी प्रहस्तन प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर सीधे ही नौभार के आयातक द्वारा संदेय होगा:

क्र.सं.	वस्तु	रुपयों में दर (प्रति टन)	
		विदेशी	तटीय
(i).	खाद्यान्न	155.27	93.16
(ii).	नमक	155.27	93.16
(iii).	उर्वरक	155.27	93.16
(iv).	उर्वरक हेतु कच्चा माल	155.27	93.16
(v).	कोयला	155.27	93.16

टिप्पणी:

उक्त निर्धारित प्रहस्तन प्रभार जिनके लिए मिश्रित प्रभार है, वे ये हैं: (i) नौभरण सहित जलयान से नौभार को उतराई तथा भंडारण स्थल तक उसका अंतरण 5 दिनों को मुक्त अवधि तक चित्तियाई में भंडारण तथा आगामी नौभार के मामले में ट्रकों पर उनकी लदाई और (ii) चित्तियाई पर ट्रकों से नौभार की उतराई, 15 दिनों की अवधि तक चित्तियाई में भंडारण, लदाई स्थल पर नौभार का अंतरण तथा नौभरण सहित जहाज पर लदाई। इस मिश्रित प्रभार में भरणघाट प्रभार तथा श्रमिक आपूर्ति, जहां आवश्यक हो शामिल है।

- (iii). इसी अवधि के दौरान विभिन्न अन्य महापत्तनों के लिए प्राधिकरण अनुमोदित अन्य दरमानों को 18 जनवरी 2018 के ई-मेल द्वारा प्रस्तुत किया गया:

- (क). आदेश संख्या टीएएमपी/38/2010-एमओपीटी दिनांक 18 फरवरी, 2011
 (ख). आदेश संख्या टीएएमपी/32/2010-वीपीटी दिनांक 29 नवंबर, 2010
 (ग). आदेश संख्या टीएएमपी/54/2009- वीपीटी दिनांक 04 मई, 2010
 (घ). आदेश संख्या टीएएमपी/27/2009-टीपीटी दिनांक 23 फरवरी, 2010

उक्त आदेशों में अनुमोदित दरमानों का अध्ययन करने से, उनमें ऐसा कोई खंड नहीं पाया गया है जैसा डीपीटी में तूना टेकरा स्थित शुष्क बल्क टर्मिनल के मामले में कार्गो प्रहस्तन प्रभारों के अंतर्गत दिया गया है।

- (iv). (क). इस प्रकार, एकेबीटीपीएल ने इस प्राधिकरण से यह अनुरोध किया कि इस खंड को पूर्णतः हटा दिया जाये या इसका निम्नवत् पुनर्गठित किया जाये:

“कार्गो प्रहस्तन प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर कार्गो के आयातक, निर्यातक, पत्तन प्रयोक्ता या प्रहस्तन एजेंट द्वारा विनिहित कार्गो पर संदेय होंगे।”

- (ख). ऐसे भी दृष्टांत हैं जहां व्यापार प्रथाओं के कारण आयातक पत्तन का ग्राहक नहीं होता। कुछ व्यापारी अथवा एजेंट होते हैं जो पत्तन के ग्राहक के रूप में कार्य करते हैं और तदनुसार

17 अगस्त, 2010 के मूल आदेश और एकेबीटीपीएल के नाम में दरमानों की अधिसूचना में यह संशोधन चाहा गया है।

4. एकेबीटीपीएल से प्राप्त प्रत्येक संदर्भ की प्रति हमारे 09 फरवरी, 2018 के पत्र के द्वारा डीपीटी को 16 फरवरी, 2018 तक बिंदु-वार विशिष्ट टिप्पणियां देने को कहा गया। इसके पश्चात् 01 मार्च 2018 को अनुस्मारक भी भेजा गया।

5. प्रत्युत्तर में, डीपीटी ने 12 मार्च, 2018 के अपने ई-मेल में निम्नलिखित उत्तर दिया। उनके उत्तर के संगत बिंदु निम्नवत् पुनरुद्धरित किये जा रहे हैं:

- (i). डीपीटी में बीओटी आधार पर 4 बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ संख्या 13 से 16 के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क अनुमोदित करते समय प्राधिकरण ने अपने 14 अक्टूबर, 2018 के आदेश 12 नवंबर, 2008 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 192, के अनुलग्नक IV में अर्थात् बहुउद्देशीय कार्गो टर्मिनलों के लिए प्रशुल्क की अनुसूची 3 कार्गो प्रहस्तन प्रभारों के अंतर्गत निम्नलिखित वाक्य अंतर्विष्ट किया: *“कार्गो प्रहस्तन प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर प्रत्यक्ष रूप से कार्गो के आयातक द्वारा विनिहित कार्गो पर संदेय होंगे”*। इस प्रकार डीपीटी ने उक्त सोपाधिकता का प्रस्ताव नहीं किया था।
- (ii). इसके अतिरिक्त, डीपीटी के 14 अक्टूबर, 2008 का आदेश पारित करते समय, देखें पैरा 9 (v), इस प्राधिकरण ने परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) के लौह अयस्क और तथा कोयला बर्थों की बर्थ किराया दरों का 12 अगस्त 2008 (14 जुलाई 2008) के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2008-पीपीटी के अनुमोदन का प्राधिकरण द्वारा संदर्भ दिया गया था। पीपीटी के 12 अगस्त, 2008 के आदेश के अनुलग्नक VI अर्थात् पीपीटी पर कोयला टर्मिनल के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क अनुसूची का अवलोकन करने पर उसी वाक्य को कार्गो प्रहस्तन प्रभार शीर्षक के अंतर्गत भी निर्धारित किया गया है अर्थात् *“कार्गो नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर प्रत्यक्ष रूप से कार्गो के आयातक द्वारा प्रहस्तन प्रभार विनिहित कार्गो पर संदेय होंगे”*।
- (iii). इस प्रकार उपरोक्त से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि डीपीटी में बीओटी आधार पर 4 बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ संख्या 13 से 16 के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क अनुमोदित करते समय इस प्राधिकरण ने अपने 14 अक्टूबर, 2018 के आदेश में इस प्राधिकरण ने उसी वाक्य को, जैसा ऊपर दिया गया है, 12 अगस्त, 2008 के आदेश द्वारा पीपीटी की लौह अयस्क और कोयला बर्थों के अपफ्रंट प्रशुल्क में भी अनुमोदित किया।
- (iv). तदनुसार, बीओटी आधार पर कांडला पत्तन पर तूना के निकट ऑफ टेकरा में शुष्क बल्क टर्मिनल के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण के 07 जनवरी 2010 के पत्र संख्या एफए/कास्ट/1231/16 के द्वारा इस प्राधिकरण के अनुमोदन के संशोधित प्रशुल्क प्रस्ताव में डीपीटी ने प्रस्तावित प्रशुल्क दरमानों में, सेवाएं प्रदान करने की सोपाधिकताओं के साथ, अनुलग्नक के रूप में, डीपीटी में बीओटी आधार पर बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ संख्या 13 से 16 के लिए 14 अक्टूबर, 2008 के प्रशुल्क आदेश के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का प्रस्ताव किया था:

“कार्गो प्रहस्तन प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर प्रत्यक्ष रूप से कार्गो के आयातक द्वारा विनिहित कार्गो पर संदेय होंगे”।

6. 12 मार्च, 2018 के पत्र में डीपीटी द्वारा दिये गए उक्त उत्तर से डीपीटी द्वारा डीपीटी में बीओटी आधार पर बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ संख्या 13 से 16 के लिए 14 अक्टूबर, 2008 के प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/35/2008-केपीटी द्वारा अनुमोदित दरमानों में इसी प्रकार निर्धारित उपलब्ध वाक्य का उदाहरण देते हुए

बीओटी आधार पर शुष्क बल्क कार्गो के लिये अपफ्रंट प्रशुल्क चाहते समय उक्त प्रस्तावित उपबंध को शामिल करने की पृष्ठभूमि का हवाला दिया जिस का डीपीटी ने पीपीटी में कोयला और लौह अयस्क बर्थों के लिए 12 अगस्त, 2008 के इस प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/18/2008-पीपीटी के द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क में निर्धारित किये गये वाक्य का अनुसरण किया। तथापि, डीपीटी ने एकेबीटीपीएल द्वारा अपने 18 जनवरी, 2018 के पत्र और 18 जनवरी, 2018 के ई-मेल में प्रस्तावित संशोधनों की विशिष्ट टिप्पणियां नहीं दीं। इसलिए, डीपीटी को हमारे 28 मार्च, 2018 के पत्र के द्वारा डीपीटी को एकेबीटीपीएल द्वारा अपने 18 जनवरी, 2018 के पत्र और 18 जनवरी, 2018 के ई-मेल में प्रस्तावित संशोधनों की विशिष्ट टिप्पणियां देने का पुनः अनुरोध किया गया। इसके पश्चात्, 26 जुलाई, 2018 को अनुस्मारक भी भेजा गया।

7. प्रत्युत्तर में, डीपीटी ने 03 अगस्त, 2018 के अपने पत्र के द्वारा स्पष्ट किया कि डीपीटी में वर्तमान प्रथा के अनुसार, घाटशुल्क ऑन-बोर्ड श्रम प्रभारों आदि सहित कार्गो संबंधी प्रभार आयातक/निर्यातक अथवा उनके अधिकृत एजेंटों द्वारा ही दिये जा रहे हैं।

8.1. इस प्रकार, संक्षेप में, एकेबीटीपीएल द्वारा किया गया अभ्यावेदन अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के अंतर्गत बीओटी आधार पर तूना-टेकरा स्थित शुष्क बल्क टर्मिनल के लिए इस प्राधिकरण के 17 अगस्त, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी द्वारा अनुमोदित अनुसूची 3 कार्गो प्रहस्तन प्रभारों के अंतर्गत अपफ्रंट दरमानों में निर्धारित निम्नलिखित उपबंध के इर्द-गिर्द ही धूम रहा है:

“कार्गो प्रहस्तन प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर प्रत्यक्ष रूप से कार्गो के आयातक द्वारा विनिहित कार्गो पर संदेय होंगे।”

8.2. एकेबीटीपीएल द्वारा इस प्राधिकरण के 17 अगस्त, 2018 के आदेश द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क दरमानों और 02 जनवरी, 2015 के एकेबीटीपीएल के नाम से आदेश संख्या टीएएमपी/59/2014-केपीटी में अधिसूचित दरमानों में भी उक्त उपबंध के संशोधन चाहने के लिए निम्नलिखित कारण/औचित्य दिये हैं:

- (i). ऐसे भी दृष्टांत हैं जहां व्यापार प्रथाओं के कारण आयातक पत्तन का प्रत्यक्ष ग्राहक नहीं हो सकता।
- (ii). कुछ व्यापारी अथवा एजेंट होते हैं जो पत्तन के ग्राहक के रूप में कार्य करते हैं।

8.3. उक्त कारण देते हुए, एकेबीटीपीएल द्वारा यह अनुरोध किया गया है तो वर्तमान उपबंध को पूर्णतः हटा दिया जाये या इस “आयातक” शब्द के बाद “निर्यातक, पत्तन प्रयोक्ता अथवा प्रहस्तन एजेंट” शब्द अंतर्विष्ट करते हुए पुनर्गठित किया जाए। एकेबीटीपीएल द्वारा प्रस्तावित आशोधित उपबंध इस प्रकार होगा:

“कार्गो प्रहस्तन प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर कार्गो के आयातक, निर्यातक, पत्तन प्रयोक्ता या प्रहस्तन एजेंट द्वारा विनिहित कार्गो पर संदेय होंगे।”

8.4. इस प्राधिकरण द्वारा अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 के अंतर्गत अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क डब्ल्यूपीआई के 60% वार्षिक सूचकांकन के अधीन होते हैं। जबकि, इस प्राधिकरण द्वारा अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2008 के अंतर्गत अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क की समीक्षा की कोई गुंजाईश नहीं है, वर्तमान मामला अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क में कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं चाहता। मामला आयातक से कार्गो प्रहस्तन प्रभारों को एकत्र करने के बारे में इस प्राधिकरण के 17 अगस्त, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी के द्वारा अनुमोदित वर्तमान दरमानों के खंड 3 के शीर्षक के निर्धारण में अपर्याप्तता के कारण उठा है। इस शीर्षक में निर्यातक और अधिकृत एजेंट शामिल नहीं है, जैसा एकेबीटीपीएल ने बताया है। एकेबीटीपीएल द्वारा उठाया गया मुद्दा यह है कि इसमें अनभिप्रेत टंकण भूल हुई है जो वास्तव में सही नहीं है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि तूना के निकट ऑफ टेकरा में शुष्क बल्क कार्गो के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क की परामर्श प्रक्रिया के दौरान, मुंद्रा पोर्टल एंड सेज़ लिमिटेड, जो एकेबीटीपीएल के

हितधारकों में से एक है, से भी परामर्श किया गया था। किसी भी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन/ भावी बोलीदाता, मुद्रा पोर्ट्स एंड सेज़ लिमिटेड सहित, जो एकेबीटीपीएल के हितधारकों में से एक है, ने इस मुद्दे को मामले के संसाधन के दौरान नहीं उठाया, जिसे अब एकेबीटीपीएल द्वारा उठाया गया है। अतः इस प्राधिकरण ने डीपीटी के अपफ्रंट प्रशुल्क प्रस्ताव का अनुमोदन किया था जो 17 अगस्त, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी के रूप में पराकाष्ठा पर पहुंचा जिसमें अनुसूची-3 कार्गो प्रहस्तन प्रभार के शीर्षक के अंतर्गत यह उपबंध है “*कार्गो प्रहस्तन प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर प्रत्यक्ष रूप से कार्गो के आयातक द्वारा विनिर्दिष्ट कार्गो पर संदेय होंगे*”।

इस मुद्दे को एकेबीटीपीएल द्वारा तब भी नहीं उठाया गया जब एकेबीटीपीएल के नाम से सूचकांकित अपफ्रंट प्रशुल्क की अधिसूचना की वांछा की गई। इस प्राधिकरण ने एकेबीटीपीएल के नाम से उक्त दरमानों को डीपीटी से परामर्श के पश्चात् 02 जनवरी, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/59/2014-केपीटी द्वारा 17 अगस्त 2010 के आदेश में अधिसूचित अपफ्रंट प्रशुल्क को विधिवत् सूचकांकित किया था जिनमें उक्त उल्लिखित उपबंध निर्धारित है।

8.5. जैसा डीपीटी ने ठीक ही कहा है कि, कांडला में तूना के निकट ऑफ टेकरा स्थित शुष्क बल्क टर्मिनल के अधिकतम अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण का अनुमोदन चाहते समय, पत्तन ने बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ संख्या 13 से 16 के लिए डीपीटी के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में अनुमोदित दरमानों में उक्त उपबंध इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया था। तथापि यह अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 2008 के जारी होने के पश्चात् परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) स्थित लौह अयस्क और कोयला टर्मिनल के अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारण से संबंधित प्रस्ताव का अनुमोदन करते समय इस प्राधिकरण द्वारा 14 जुलाई, 2008 के प्रथम अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/18/2008-पीपीटी में उपलब्ध निर्धारण से प्रवाहित हुआ जो 26 फरवरी 2008 से प्रभावी हुए थे। उक्त उपबंध पीपीटी स्थित लौह अयस्क टर्मिनल और कोयला टर्मिनल के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीटी) परियोजनाओं के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क दरमानों में निर्धारित किया गया था और तत्पश्चात्, इसे बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ संख्या 13 से 16 के लिए डीपीटी की पीपीटी परियोजना के अपफ्रंट प्रशुल्क अनुमोदन में अंतर्विष्ट किया गया था।

9.1. यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि एकेबीटीपीएल द्वारा चाहा गया वर्तमान संशोधन 17 अगस्त, 2010 के अपफ्रंट प्रशुल्क आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपफ्रंट प्रशुल्क आकलित वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) में संशोधन नहीं मांगता। एकेबीटीपीएल द्वारा चाहा गया संशोधन वर्तमान उपबंध में विस्तार के लिए है कि दीनदयाल पत्तन में व्यापार की सामान्य प्रथा के अनुसार जिससे कार्गो प्रहस्तन प्रभार एकत्र किये जा सकते हैं। डीपीटी ने भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान प्रथा के अनुसार, घाटशुल्क ऑन-बोर्ड श्रम प्रभारों आदि सहित कार्गो संबंधी प्रभार आयातक/निर्यातक अथवा उनके अधिकृत एजेंटों द्वारा ही दिये जा रहे हैं। अतः 17 अगस्त, 2010 के उक्त आदेश द्वारा अनुमोदित दरमान के खंड 3 के शीर्षक और 02 जनवरी, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/59/2014-केपीटी द्वारा एकेबीटीपीएल के नाम से अधिसूचित सूचकांकित दरमान में भी संशोधन उचित पाया जाता है।

9.2. यहां यह भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि अनुसूची 3 - कार्गो प्रहस्तन प्रभार के नीचे दी गई टिप्पणी मिश्रित प्रभारों के अंतर्गत आने वाली सेवाएं दी गई हैं जिसके अंतर्गत जहाज से कार्गो उतारना निशुल्क भंडारण और आयातित कार्गो का जब तक जहाज से ट्रक पर लदान नहीं कर दिया जाता तब तक और स्टैक याई में ट्रक से कार्गो लदान सेवाएं आती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि मिश्रित प्रहस्तन दर आयात और निर्यात के दोनों चक्रों को कवर करती है। प्रहस्तन प्रभारों की वसूली के बारे में आयातकों का उल्लेख है निर्यातकों से नहीं।

9.3. प्रसंगवश, यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि हाल ही में परादीप इंटरनैशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (पीआईसीटीपीएल) ने भी जो पीपीटी पर बीओटी प्रचालक है, जिसके नाम से इस प्राधिकरण ने पीपीटी स्थित बहुप्रयोजनीय बर्थ के विकास के लिए 19 फरवरी, 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/10/2014-पीपीटी के द्वारा अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क के आधार पर 24 अप्रैल 2018 को इस प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/17/2018-पीआईसीटीपीएल के द्वारा सूचकांकित दरमान अनुमोदित किये गए थे, इसी मामले में इस प्राधिकरण को संपर्क किया है कि उनके अनुमोदित दरमानों में “आयातक” शब्द के पश्चात् “निर्यातक” शब्द जोड़ते हुए संशोधन किया जाये। इस

प्राधिकरण ने मामले का परीक्षण करने के पश्चात् “निर्यातक” शब्द जोड़ते हुए 31 जुलाई 2018 को संशोधन संख्या टीएएमपी/17/2018-पीआईसीटीपीएल जारी किया।

10. वर्तमान प्रक्रिया में, जब डीपीटी से टिप्पणियां मंगायी गईं, पत्तन ने स्पष्ट किया कि डीपीटी में वर्तमान प्रथा के अनुसार, घाटशुल्क ऑन-बोर्ड श्रम प्रभारों आदि सहित कार्गो संबंधी प्रभार आयातक/निर्यातक अथवा उनके अधिकृत एजेंटों द्वारा ही दिये जा रहे हैं।

डीपीटी ने प्रचलित प्रथा के बारे में डीपीटी के स्पष्टीकरण के आधार पर इस प्राधिकरण ने 17 अगस्त, 2010 के अप्रकृत प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी और एकेबीटीपीएल के नाम से अधिसूचित दरमानों में निर्धारित वर्तमान उपबंध में “निर्यातक या उनके अधिकृत एजेंट” “आयातक” शब्द के पश्चात् जोड़ने का निर्णय लिया।

11. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणों से तथा किये गए सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण 17 अगस्त, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी और एकेबीटीपीएल के नाम से अधिसूचित सूचकांकित आदेश संख्या टीएएमपी/59/2014-केपीटी दिनांक 02 जनवरी 2015 में निम्नलिखित संशोधनों का अनुमोदन करता है:

- (i). अनुसूची 3 - कार्गो प्रहस्तन प्रभार के अंतर्गत 17 अगस्त, 2010 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2009-केपीटी में तूना के निकट ऑफ टेकरा में शुष्क बल्क कार्गो के विकास के लिए अप्रकृत प्रशुल्क अनुसूची में वर्तमान शीर्षक को निम्नवत् आशोधित किया जाता है:-

“कार्गो प्रहस्तन प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर प्रत्यक्ष रूप से कार्गो के आयातक/निर्यातक या उनके अधिकृत एजेंटों द्वारा विनिहित कार्गो पर संदेय होंगे”।

- (ii). 02 जनवरी, 2015 के आदेश संख्या टीएएमपी/59/2014-केपीटी में, एकेबीटीपीएल के नाम से अधिसूचित दरमान में अनुसूची 3 - कार्गो प्रहस्तन प्रभार के अंतर्गत निर्धारित वर्तमान शीर्षक को निम्नवत् आशोधित किया जाता है:

“कार्गो प्रहस्तन प्रभार नीचे विनिर्दिष्ट दरों पर प्रत्यक्ष रूप से कार्गो के आयातक/निर्यातक या उनके अधिकृत एजेंटों द्वारा विनिहित कार्गो पर संदेय होंगे”।

12. तदनुसार, यह प्राधिकरण, एकेबीटीपीएल के 18 जनवरी, 2018 के पत्र और 18 जनवरी 2018 के ई-मेल से प्राप्त अभ्यावेदन का, निपटान करता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
[विज्ञापन-III/4/असा./524/18]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 25th January, 2019

No.TAMP/59/2014-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the reference received from Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. (AKBTPL) as regards amendment in TAMP Order no.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 and Order no.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015, as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**Case No. TAMP/59/2014-KPT****M/s.Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd.**

- - -

Applicant**QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 18th day of January 2019)

This matter relates to a reference received from Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. (AKBTPL) vide its letter dated 18 January 2018 and email dated 18 January 2018 for amendment in TAMP Order no.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 and Order no.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015.

2.1. This Authority had passed an Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 fixing upfront tariff for development of Dry Bulk Terminal off Tekra near Tuna following the Upfront Tariff Guidelines of 2008 based on the proposal of the (then) Kandla Port Trust (KPT). This Order was notified in the Gazette of India on 02 November 2010 vide Gazette No.285.

2.2. As per clause 2.8 of the Upfront Tariff Guidelines 2008 and para 11.1 of the said Upfront Tariff Order dated 17 August 2010, the Upfront Tariff approved by this Authority is for the period of 30 years subject to annual indexation of 60% of Wholesale Indexed Price (WPI).

2.3. The DPT has awarded the project for development of dry bulk terminal off Tekra near Tuna based on the Upfront Tariff approved by this Authority to AKBTPL. The Concession Agreement (CA) dated 27 June 2012 was entered between the DPT and the AKBTPL.

2.4. As per Article 8.1 of CA relating to Tariff, Licensee shall be entitled to collect Tariff from the users of the Project Facilities and Services as per the Tariff Notification. The SOR approved by this Authority vide Order dated 17 August 2010 is attached as Appendix-12 in the CA.

2.5. Subsequently, as per Clause 2.9.1 of the Upfront Tariff Guidelines 2008 and para 11.2 of the Order dated 17 August 2010, AKBTPL had filed the proposal for notification of indexed SOR in their name. Accordingly, this Authority has vide Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015 notified the SOR in the name of the AKBTPL duly indexing the upfront tariff notified in the 17 August 2010 Order, after consulting DPT vide our letter No.TAMP/59/2014-KPT dated 22 October 2014.

3. With reference to the said Orders, the AKBTPL vide its letter dated 18 January 2018 and email dated 18 January 2018 has made the following submissions:

- (i). With reference to the Order no.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 and Order no.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015 and subsequent amendment, there is inadvertent typographical error in the said Orders issued by the Authority for Dry Bulk Terminal near Tuna outside Kandla Creek at DPT on Build, Operate and Transfer (BOT) basis.
- (ii). Clause no.3 of the SOR approved by the Authority, prescribing Cargo Handling Charges is reproduced below for reference and first two sentence is highlighted in bold:

3. CARGO HANDLING CHARGES:

The cargo handling charges shall be payable on the manifested cargo directly by the importer of cargo at the rates specified below:

Sr. No.	Commodity	Rate in ₹ (per tonne)	
		Foreign	Coastal
(i).	Foodgrains	155.27	93.16
(ii).	Salt	155.27	93.16
(iii).	Fertilizer	155.27	93.16
(iv).	Fertilizer raw materials	155.27	93.16
(v).	Coal	155.27	93.16

Note:

The handling charges prescribed above is a composite charge for (i) unloading of the cargo from the vessel including stevedoring and transfer of the same upto the point of storage, storage at the stackyard upto a free period of 5 days and loading on to trucks in respect of import cargo and (ii) unloading of the cargo from the trucks at the stackyard, storage at the stackyard upto a period of 15 days, transfer the cargo to the loading point and loading onto the ship including stevedoring. This composite charge includes wharfage and supply of labour, wherever necessary.

- (iii). Following other Scale of Rates approved by the Authority for Terminals at various other Ports around same period, falling under 2008 Guidelines are furnished by email dated 18 January 2018:

- (a). Order No.TAMP/38/2010-MOPT dated 18 February 2011.
- (b). Order No.TAMP/32/2010-VPT dated 29 November 2010.
- (c). Order No.TAMP/54/2009-VPT dated 04 May 2010.
- (d). Order No.TAMP/27/2009-TPT dated 23 February 2010.

Going through the SORs approved in the above mentioned Orders, there is no such mention of the clause as mentioned under Cargo Handling Charges in case of Dry Bulk Terminal at Tuna Tekra at DPT.

- (iv). (a). Thus, accordingly AKBTPL hereby requests the Authority that the clause be removed completely or rephrased as under:
- “The cargo handling charges shall be payable on the manifested cargo by the importer, exporter, port user or handling agent of cargo at the rates specified below:”*
- (b). There have been instances where the importer is not the direct customer of the port due to trade practices. There are traders and agents who act as customers of the port and accordingly this amendment is sought in the original Order dated 17 August 2010 and notification of the SOR in the name of the AKBTPL.

4. A copy each of the reference received from the AKBTPL was forwarded to DPT for point-wise specific comments by 16 February 2018 vide our letter dated 09 February 2018. This was also followed by reminder dated 01 March 2018.

5. In response, the DPT vide its e-mail dated 12 March 2018 has responded. The relevant points of its response are as follows:

- (i). TAMP while approving the upfront tariff for 4 multipurpose cargo berth Nos.13th to 16th on BOT basis at DPT vide its Order dated 14 October 2008, Gazette notification No. 192 dated 12 November 2008, had in the Annexure IV i.e. Tariff for Multipurpose cargo terminals under Schedule 3 Cargo handling charges, inserted the following phrase:
- “The cargo handling charges shall be payable on the manifested cargo directly by the importer of cargo at the rates specified below:”*. Thus, DPT had not proposed the above conditionality.
- (ii). Further, while passing the Order dated 14 October 2008 of DPT, vide Para 9 (v), TAMP had given reference of Authority approving the berth hire rates for the iron ore and coal berths of the Paradip Port Trust (PPT) vide Order No.TAMP/18/2008-PPT dated 12 August 2008 (14 July 2008). On perusal of the PPT's Order dated 12 August 2008, Annex-VI, i.e. Upfront tariff schedule for the Coal Terminal at PPT, the same Phrase is prescribed under the heading Cargo handling charges, i.e. *“The cargo handling charges shall be payable on the manifested cargo directly by the importer of cargo at the rates specified below:”*.
 - (iii). Thus, from the above it can be construed that before approving the Upfront tariff for multipurpose cargo berth nos.13th to 16th on BOT basis at DPT vide Order dated 14 October 2008, the Authority had approved the same Phrase as given above in upfront tariff approved for iron ore and coal berths of PPT vide Order dated 12 August 2008.
 - (iv). Accordingly, in the revised tariff proposal sent to the Authority for approval vide letter No.FA/Cost/1231/16 dated 07 January 2010 for upfront tariff setting for the Dry Bulk Terminal off Tekra near Tuna at Port of Kandla on BOT basis, DPT in the Proposed tariff Scale of Rates alongwith conditions for providing the services placed as Annexure-VIII, had proposed the following Phrase as per the tariff Order dated 14 October 2008 for multipurpose cargo berth nos.13th to 16th on BOT basis at DPT, *“The cargo handling charges shall be payable on the manifested cargo directly by the importer of cargo at the rates specified below:”*

6. The above reply furnished by DPT vide its letter dated 12 March 2018 gives background of the inclusion of said proposed provision by DPT while seeking upfront tariff for Dry Bulk Terminal at Tuna Tekra on BOT basis citing similar prescription available in the SOR approved by the Authority vide Order No.TAMP/35/2008-KPT dated 14 October 2008 for multipurpose cargo berth Nos.13th to 16th on BOT basis at DPT which followed the prescription made in the upfront tariff approved by the Authority vide Order No.TAMP/18/2008-PPT dated 12 August 2008 in PPT for Coal and Iron Ore Berths. The DPT has, however, not furnished its specific comments on the amendment proposed by AKBTPL vide its letter dated 18 January 2018 and email dated 18 January 2018. Therefore, DPT was again requested vide our letter dated 28 March 2018 to furnish its specific comments on the amendment proposed by AKBTPL vide its letter dated 18 January 2018 and email dated 18 January 2018. This was also followed by reminder dated 26 July 2018.

7. In response, the DPT vide its letter dated 03 August 2018 has clarified that as per existing practice in DPT, the cargo related charges including wharfage, on board labour charges etc. are being paid by the importer / exporter or by their authorized agents.

8.1. Thus, in short the representation made by the AKBTPL revolves around the following provision prescribed in the Upfront SOR under the Schedule 3 – Cargo Handling Charges approved by this Authority vide Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 for the Dry Bulk Terminal at Tuna Tekra on BOT basis under the Upfront Tariff Guidelines of 2008:

“The cargo handling charges shall be payable on the manifested cargo directly by the importer of cargo at the rates specified below:”

8.2. The AKBTPL has given the following reasons / justifications for seeking amendment as regards above said provision in the upfront tariff SOR approved by this Authority vide said Order dated 17 August 2010 and also in the indexed SOR notified in the name of the AKBTPL vide Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015:

(i). There have been instances where in the importer may not be the direct customer of the port due to trade practices.

(ii). There may be traders and agents who act as customers of the port.

8.3. Citing the above reasons, the request made by AKBTPL is to either delete the existing said provision completely or rephrase it to include the words “exporter, port user or handling agent”, after the word “importer”. The modified provision proposed by the AKBTPL is as follows:

“The cargo handling charges shall be payable on the manifested cargo by the importer, exporter, port user or handling agent of cargo at the rates specified below:”

8.4 The upfront tariff approved by this Authority under Upfront Tariff Guidelines 2008 is only subject to annual indexation at 60% of the WPI. While there is no scope for review of the upfront tariff approved by this Authority under the Upfront Tariff Guidelines 2008, the instant case does not warrant any change or amendment in the approved Upfront Tariff. The matter arises due to inadequacy in the prescription of caption of Section 3 in the existing SOR approved by this Authority vide Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 about collection of the cargo handling charges from importer. The caption does not cover exporter and authorized agent as stated by AKBTPL. The point made by AKBTPL that there is an inadvertent typographical error is not factually correct. It is relevant here to state that during the consultation process of Upfront Tariff for Dry Bulk Terminal off Tekra near Tuna, Mundra Port & SEZ Limited who is one of the stakeholders of AKBTPL was also consulted. None of the users / user association / prospective bidders including Mundra Port & SEZ Limited who is one of the stakeholders of AKBTPL raised this point, now, brought out by AKBTPL, while processing of the case. Hence, this Authority had approved the Upfront Tariff proposal of DPT which is culminated into the Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 which included the provision *“The cargo handling charges shall be payable on the manifested cargo directly by the importer of cargo at the rates specified below:”* under the title of schedule 3 – Cargo Handling Charges.

This point was not raised by AKBTPL even while seeking notification of indexed Upfront Tariff in name of AKBTPL. This Authority has vide Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015 notified the said SOR in the name of the AKBTPL duly indexing the upfront tariff notified in the Order dated 17 August 2010, after consulting DPT which also prescribes the above mentioned provision.

8.5. As rightly stated by the DPT, while seeking approval for fixation of upfront tariff caps for the Dry Bulk Terminal off Tekra near Tuna at Kandla, the port proposed the said provision which was prescribed by this Authority in the SOR approved in the Upfront Tariff Order of DPT for 13th to 16th berths for multipurpose cargo berths. This, however, flows from prescription available in the first Upfront Tariff Order No.TAMP/18/2008-PPT dated 14 July 2008 approved by this Authority relating to fixation of Upfront Tariff for iron ore terminal and coal terminal at the Paradip Port Trust (PPT) after the issue of Upfront Tariff Guidelines 2008 which came into effect from 26 February 2008. The said provision prescribed in the Upfront Tariff SOR approved by this Authority for Public Private Partnership (PPP) projects for development of iron ore terminal and coal terminal at PPT was incorporated in the subsequent Upfront Tariff approved for the PPP project of DPT for multipurpose cargo berths at Berth Nos.13th to 16th.

9.1. It is relevant to state that the present amendment sought by the AKBTPL does not entail amendment in the approved Upfront Tariff or on the estimated Annual Revenue Requirement (ARR) approved by this Authority in the upfront tariff Order dated 17 August 2010. The amendment sought by AKBTPL is to elaborate the existing provision to capture from whom cargo handling charges are collectable as per the usual practice of trade at the Deendayal Port. The DPT has also clarified that as per existing practice in DPT, the cargo related charges including wharfage, on board labour charges etc. are being paid by the importer / exporter or by their authorized agents. Hence, there is a merit to amend the caption of Section 3 of the upfront SOR approved vide said Order dated 17 August 2010 and also in the indexed SOR notified in the name of the AKBTPL vide Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015.

9.2. It is also relevant here to state that note under schedule 3 - Cargo handling charges prescribes the services covered under the composite charges which covers services towards unloading of cargo from ship, free storage and ship till loading onto truck from import cargo and for unloading of cargo from truck at stack yard, free storage and loading cargo onto vessels. This means the composite handling rate covers both import cycle and export cycle. The title about collection of handling charges mentions about importer but not from exporter.

9.3. Incidentally, recently even Paradip International Cargo Terminal Private Limited (PICTPL) who is a BOT operator at PPT in whose name the indexed SOR was approved by this Authority vide Order No.TAMP/17/2018-PICTPL dated 24 April 2018 based on the Reference Tariff approved by this Authority vide Order No.TAMP/10/2014-PPT dated 19 February 2014 for development of multipurpose Berth at PPT to handle containers and clean cargo had approach this Authority on the same matter and had requested for amendment in their SOR to include the words “exporter” after the word “importer” in the existing provision in their SOR. This Authority after examining the matter has issued a corrigendum No.TAMP/17/2018-PICTPL dated 31 July 2018 including the word “exporter”.

10. In the current exercise when comments of DPT were sought, the port has clarified that as per existing practice at DPT, cargo related charges including wharfage, on Board labour charges are being paid by importer / exporter or by their authorized agent.

Based on the clarification of DPT about the practice in vogue in DPT, this Authority decides to elaborate the existing provision prescribed in the upfront tariff Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 and SOR notified in the name of the AKBTPL to include the words “/ exporters or their authorized agents” after the word “importers”.

11. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the following amendments in the SOR of upfront tariff Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 and indexed SOR notified in the name of AKBTPL vide Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015:

- (i). **The existing caption under Schedule 3 - Cargo Handling Charges prescribed in upfront tariff schedule for development of Dry Bulk Terminal off Tekra near Tuna in the Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 is modified as follows:**

“The cargo handling charges shall be payable on the manifested cargo directly by the importers / exporters or their authorized agent at the rates specified below:”

- (ii). **The existing caption under Schedule 3 - Cargo Handling Charges prescribed in SOR notified in the name of the AKBTPL in the Order No.TAMP/59/2014-KPT is modified dated 02 January 2015 is modified as follows:**

“The cargo handling charges shall be payable on the manifested cargo directly by the importers / exporters or their authorized agent at the rates specified below:”

12. Accordingly, this Authority disposes of the representation of the AKBTPL dated 18 January 2018 and email dated 18 January 2018.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./524/18]